कीटनाशकों की अनुपलब्धता

6351. श्री प्रताप भानु शर्मा: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत ढाई वर्षों के दौरान कीटनाशक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को असरदार ढंग से लागू नहीं किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं जहां कीटनाशकों का छिड़काव उतनी मात्रा में नहीं किया गया जितनी मात्रा में केन्द्र द्वारा निर्धारित की गई थी और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार इस राष्ट्रीय महत्व के इस स्वास्थ्य कार्यक्रम को और अधिक सक्रियता से लागू कराने के लिए क्या प्रयास कर रही है। ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर): (क) जी नहीं । वास्तव में पिछले तीन वर्षों में मलेरिया की घटनाओं में जो कमी आई है, वह इस प्रकार है:--

वर्ष	मलेरिया के पाजेटिव रोगियों की संख्या
1976	6467215
1977	.4740900
1978	4144385
1979	2808222 (अनन्तिम)

कुछेक कीटनाशक दवाओं की कमी होने के बावजूद मलेरिया की घटनाओं में कमी आई है।

(ख) गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों में कीटनाशक दवाओं का यथेष्ट छिड़काव नहीं किया जा सका। ऐसा कुछ तो कीटनाशक दवाओं की कमी के कारण हुआ है और कुछ प्रशासनिक और अन्य कठिनाइयों के कारण हुआ है।

(ग) 1980 के दौरान कुछ कीटनाशक दवाओं का आयात करके उन्हें उचित मात्रा में उपलब्ध कराने के प्रबन्ध कर दिये गये हैं। राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे सभी चरणों में पर्यवेक्षण और निगरानी कार्यों में तेजी लाएं तथा रोग को फैलने से रोकने के लिए एकजुट होकर प्रयास करें और यह सुनिश्चित करें कि मलेरिया की घटनाओं और उससे होने वाली मौतों में यथेष्ट कमी आए। उनसे यह भी आग्रह किया गया है कि वे देखें कि 1980 के दौरान् मलेरिया की घटनाओं में कम से कम 30 प्रतिशत कमी अवश्य आ जाए ।

Welfare Schemes for Agricultural Labour in Karnataka

6352. SHRI S. M. KRISHNA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state the major welfare schemes so far approved by the Central Government for the Welfare of Agricultural labour in Karnataka during the last three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T ANJIAH): The major welfare schemes approved by the Central Government for the welfare of rural labour in Karnataka include the rehabilitation programme for bonded labour, the rural health scheme, the Integrated Rural Development Programmes, the small farmers development programmes, the food for work programme and training programmes for the rural youth. These programmes benefit the rural labour, of which agricultural labour forms a part.

From the details available, under the rehabilitation programme for Bonded Labour, the following amounts were released to the Government of Karnataka:—

1978-79	Rs. 10.28 lakhs
1979-80	Rs. 6.00 lakhs
1980-81	Rs. 5.82 lakhs

Under the Integrated Rural Development Programme administered by the Ministry of Rural Reconstruction, the following amounts were released to Karnataka:

1978-79	Rs. 256.30 lakhs
1979-80	Rs. 215.65 lakhs